



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2017/ चैत्र 20, 1939

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2017/CHAITRA 20, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

न्यू शिपर समीक्षा

विषय मेसर्ज तारीक ग्लॉस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) के संबंध में पाकिस्तान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर)

फा. सं. 15/16/2015-डीजीएडी.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने की जांच शुरूआत करने संबंधी दिनांक 11 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 14/25/2012-डीजीएडी द्वारा सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “4 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों सम्मिलित) के रेंज की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मामूली मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है” (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा

गया है) से संबंधित पाटन-रोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए उक्त जांच परिणाम में निर्धारित दर पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था और दिनांक 11 दिसंबर, 2014 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी) के द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया था।

3. मेसर्स तारीक ग्लॉस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "न्यू शिपर" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें पाकिस्तान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित दिनांक 11 दिसंबर, 2014 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी) के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) करने का अनुरोध किया गया है।

4. अधिनियम और पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नगत निर्यातक देश में किसी भी ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए पाटन के विशिष्ट पृथक मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ न्यू शिपर समीक्षा करें, जिसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंधित आयातों की मूल पाटन-रोधी जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं और आवेदक निर्यातक देश में किसी भी ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जो कि पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन है। आवेदक ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान अथवा अन्य संबद्ध देशों में किसी भी ऐसे निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिसके खिलाफ संबंधित उत्पाद के बारे में पाटन-रोधी उपाय लागू हैं। इसके अतिरिक्त उसने यह भी दावा किया है कि उसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

5. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की प्रथमदृष्टया जांच की है और जांच शुरू करने के समय यह पाया है कि यह सूचना पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू करने को यथोचित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत दिनांक 23 सितंबर, 2015 की अधिसूचना एफ संख्या 15/16/2015-डीजीएडी द्वारा न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की थी। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2016 (9 महीनों) तक की थी।

6. संबद्ध एनएसआर जांच की शुरुआत करने पर प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार तथा दिनांक 11 दिसंबर, 2014 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी) को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा के पूरा होने तक मेसर्स तारीक ग्लॉस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तुओं के किए गए सभी निर्यातों के संबंध में अनंतिम आकलन की सिफारिश की थी।

7. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 53/2015-सीमाशुल्क द्वारा एनएसआर जांच के पूरा होने तक मेसर्स तारीक ग्लॉस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों के संबंध में अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया था।

ख. प्रक्रिया

8. वर्तमान जांच के संबंध में निम्नोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

(क) प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 23 सितंबर, 2015 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसके तहत संबद्ध एनएसआर पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की गई थी।

- (ख) प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति निर्यातक प्रश्नावली की एक प्रति के साथ एनएसआर आवेदक को भेजी थी और उन्हें अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था।
- (ग) प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति दिल्ली स्थित पाकिस्तान के दूतावास को भी भेजी थी।
- (घ) प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और उन्हें अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था।
- (ङ) जाँच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में एनएसआर के आवेदक नामतः मेसर्ज तारीक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के रूप में उत्तर प्रस्तुत किया गया था।
- (च) जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और प्रदत्त सूचना के समर्थन में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के साथ और वर्तमान जांच के लिए जितना प्रासंगिक पाया गया है, उन पर प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (छ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा कर रखा हुआ है ताकि हितबद्ध पक्षकार उनका निरीक्षण कर सकें।
- (ज) प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के अनुसार 17 अगस्त और 2 नवंबर, 2016 को मौखिक सुनवाई आयोजित की थी और हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट किए गए उनके विचारों/सूचना का प्रत्युत्तर देने का भी अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।
- (झ) जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मांगी गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच की गई थी और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, समर्थक दस्तावेज मंगाए गए थे।
- (ञ) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच परिणाम के लिए आवश्यक समझे गए अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 27 मार्च, 2017 को प्रकट कर दिया गया था और उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (ट) इस जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है।
- (ठ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता के दावों की जांच की गई है। जो सूचना प्रकृति से गोपनीय है अथवा जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उसे उसके अगोपनीय संक्षिप्त विवरण सहित गोपनीय माना गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

9. वर्तमान जांच 4 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों सम्मिलित) के रेंज की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मामूली मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है, के निर्यात के बारे में है। इसका 8 अंकीय स्तर वर्गीकरण 70051090 है, हालांकि इसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 जैसे विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है और इनका निर्यात किया जाता है। सीमाशुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. आवेदक/न्यू शिपर, मेसर्ज तारीक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उत्पादक-सह-निर्यातक) के विचार

10. आवेदक के विचारों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) आवेदक ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान अर्थात् 1 अक्टूबर, 2011 से 31 दिसंबर, 2012 तक भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए थे।

- (ख) आवेदक ने अप्रैल, 2013 में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करना शुरू किया था और उसने मूल जांच की जांच अबधिक के बाद 12 जुलाई, 2013 से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात करने शुरू किए थे।
- (ग) आवेदक से संबंधित कोई भी कंपनी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नहीं लगी हुई है। आवेदक से संबंधित किसी भी कंपनी ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान अर्थात् 1 अक्टूबर, 2011 से 31 दिसंबर, 2012 तक भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए थे।
- (घ) आवेदक पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है। साथ ही आवेदक चीन जनवादी गणराज्य के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से भी संबंधित नहीं है।
- (ङ) आवेदक ने मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष भाग लिया था और क्षति के संबंध में निवेदन किया था और याचिका पर टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। तथापि, आवेदक ने मूल जांच के समय प्रश्नावली के उत्तर इसलिए प्रस्तुत नहीं किए थे क्योंकि उसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए थे।
- (च) आवेदक कंपनी ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए हैं और वह ऐसी किसी भी अन्य कंपनी से संबंधित नहीं है जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए हैं। आवेदक ने यह भी अधिप्रमाणित किया है कि वह किसी भी देश की ऐसी कंपनी से संबंधित नहीं है, जिस पर संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होता है। इस प्रकार आवेदक ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है और वह न्यू शिपर समीक्षा शुरू करवाने और शुल्क का विशिष्ट पृथक मार्जिन के निर्धारण के लिए पात्र है।
- (छ) आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है। ऐसी सभी दस्तावेजों में जिन पर गोपनीयता का दावा किया गया है, व्यवसायिक संबंधी गोपनीय सूचना निहित है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इसका घरेलू उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अथवा यह उनके लिए हानिकारक नहीं है। क्यूवाईजीएमएमसी (मेसर्स क्विनुआंगडाओ याहुआ ग्लास मशीन मेन्युफेक्चर कंपनी लिमिटेड) और आवेदक के बीच संविदा, उसमें निहित गोपनीयता के अनुच्छेद के अध्यक्षीन है और इस प्रकार इसे घरेलू उत्पादकों को भागीदार नहीं बनाया गया है।
- (ज) आवेदक ने फ्लोट ग्लास का उत्पादन करने के लिए क्यूवाईजीएमएमसी से एक नया संयंत्र अधिप्राप्त किया है और इस संयंत्र को अधिप्राप्त, स्थापित और चालू करने के लिए नकदी प्रवाह के बेहतर प्रबंधन के लिए शेयर जारी करने के माध्यम से आंशिक भुगतान किया गया है। आवेदक ने इस प्रयोजनार्थ 41,58,000 शेयर जारी करने के विकल्प को अपनाया है। इनमें से 31,18,500 शेयर क्यूवाईजीएमएमसी को जारी किए गए हैं, जो कि कंपनी के कुल शेयरों का 4.25% भाग है और 10,39,500 शेयर ग्लोबल लिंक ग्लास कंपनी को जारी किए गए हैं, जो कि एक अन्य सेवा प्रदायक कंपनी है। क्यूवाईजीएमएमसी और ग्लोबल लिंक ग्लास कंपनी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यूवाईजीएमएमसी के साथ संविदा के अनुसरण में शेयरों को जारी करने के मुद्दे का विधिवत् प्रकटन 30 जून, 2013 और 30 जून, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आवेदक के वित्तीय विवरण की टिप्पणी 13 में किया गया है। क्यूवाईजीएमएमसी ने बाद में वर्ष 2015 में इन 31,18,500 शेयरों में से 5,50,000 शेयरों का निपटान कर दिया तथा उसके परिणामस्वरूप, वर्तमान न्यू शिपर जांच के लिए जांच अवधि के दौरान क्यूवाईजीएमएमसी की शेयर धारिता में 3.5% तक की गिरावट आ गई। क्यूवाईजीएमएमसी द्वारा इस प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित शेयरों का 3.5% भुगतान मात्र था और इससे इन दोनों कंपनियों के बीच कोई

"संबंध" निर्मित नहीं हो जाता है। क्यूवाईजीएमएमसी की शेयरधारिता उसके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष निवेश नहीं था, बल्कि उसके द्वारा आपूर्ति किए गए संयंत्र और मशीनरी के लिए आंशिक भुगतान करने के लिए शेयर जारी किए गए थे। इस तथ्य के आधार पर कि आवेदक के 3.5% शेयरों की धारिता क्यूवाईजीएमएमसी की है, घरेलू उद्योग का यह तर्क देने का प्रयास है कि आवेदक उनके द्वारा "नियंत्रित" है अथवा ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन ऐसा मामला नहीं है और नियम 2 (ख) के अंतर्गत "संबंध" स्थापित करने की शर्तों पर जो कि नियमावली के अंतर्गत केवल तुलनीय मानक है, घरेलू उद्योग द्वारा परोक्ष रूप से विचार नहीं किया गया है।

- (झ) क्यूवाईजीएमएमसी का आवेदक की कंपनी के निदेशक मंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं है और उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे आवेदक पर कोई प्रभाव पड़ता हो अथवा ऐसा अधिकार प्राप्त होता हो जिससे उसे आवेदक के प्रचालन संबंधी निर्णयों पर कोई निर्देश देने का अधिकार हो। आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी किसी सामान्य प्रबंधन अथवा नियंत्रण अधीन नहीं हैं और आवेदक की विनिर्माण प्रक्रिया अथवा व्यवसाय किसी भी प्रकार से क्यूवाईजीएमएमसी पर निर्भर नहीं है। इस तथ्य को आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित किया जा सकता है। आवेदक का कोई भी उत्पाद क्यूवाईजीएमएमसी को नहीं बेचा जाता है अथवा अंतरित किया जाता है।
- (ञ) आवेदक योहुआ ग्लास ग्रुप कार्पोरेशन से संबंधित नहीं है, जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा आरोप लगाया गया है।
- (ट) घरेलू उत्पादक इस चरण में निर्यात की कमी के बारे में आवेदक के अधिप्रमाणन का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं जबकि उन्होंने मूल जांच के दौरान ऐसे प्रश्न को नहीं उठाया था। इस संबंध में घरेलू उत्पादक को अपने अधित्याग द्वारा विवद्ध किया गया है। आवेदक ने फेरो एल्वाय कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1999) 4 एससीसी 149 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है, जिसमें उसने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था कि आवेदक ऐसे विभागीय आदेश के भाग को चुनौती दे सकता है, जिसका उसने अधित्याग, विवद्ध और सम्मति के प्रतिबन्धों के बिना विगत में समर्थन किया था।
- (ठ) आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए एच एंड आर जोनसन (2005) के में मामले में सेस्टेट के निर्णय का उल्लेख किया है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत शर्त को समीक्षा की कार्यवाही के दौरान किसी भी समय पूरी किया जा सकता है और जांच शुरू होने से पहले ऐसी शर्त को पूरा करना आवश्यक नहीं था।
- (ड) घरेलू उत्पादकों को उनकी समझ को भ्रमित किया जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत "निर्यातक देश" के अंतर्गत ऐसी सभी देश शामिल हैं, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होता है और न केवल पाकिस्तान है, जहां आवेदक अवस्थित है। आवेदक ने यह निवेदन किया है कि ऐसी अवधारणा को स्वीकार करने के फलस्वरूप विशेषकर एमएमसी के लिए जहां जांच की बहुत अधिक अवधि शामिल है, न्यू शिपर समीक्षा का संचालन करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।
- (ढ) घरेलू उत्पादकों को "संबंधित" शब्दावली की समझ में भ्रमित किया गया है क्योंकि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 में ऐसा प्रतीत होता है। आवेदक क्यूवाईजीएमएमसी से संबंधित नहीं है। क्यूवाईजीएमएमसी और आवेदक के बीच संबंध पूर्णतया संविदात्मक हैं और संबद्ध संविदा जांच के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। पाटन-रोधी विधि और अन्य किसी भी कानून के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी मानक द्वारा आवेदक क्यूवाईजीएमएमसी से संबंधित नहीं है।

- (ण) घरेलू उत्पादकों ने नियम 22 के अंतर्गत "पाटन-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन" के अधिकार-क्षेत्र को गलत समझा है। आवेदक का यह आग्रह है कि नियम 22 के अंतर्गत "पाटन-रोधी शुल्क के अध्यक्षीन" का अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है जो कि *विशिष्ट पृथक् मार्जिन दर* के अध्यक्षीन हैं और जो *अवशिष्ट दरों* के अध्यक्षीन हैं। इस संबंध में आवेदक ने *एच एंड आर जोनसन इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2007 (218) ई.एल.टी 273 (पैराग्राफ 5)* पर विश्वास किया है।
- (त) जांच की चयनित अवधि विवेकाधीन नहीं है, जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा बताया गया है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 2 (1) में ऐसा प्रावधान है कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि, समय की उचित अवधि होनी चाहिए (जो कि छः महीनों से कम नहीं हो)।
- (थ) घरेलू उत्पादकों का यह दावा है कि संबद्ध न्यू शिपर समीक्षा के लिए जांच की पूर्वव्यापी अवधि का चयन विवेकाधीन है और यह कि संबद्ध समीक्षा विधि में निकृष्ट है। इस संबंध में घरेलू उत्पादकों ने *एच एंड आर जोनसन इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2007 (218) ई.एल.टी 273 (ट्रि - डेल)* के मामले का हवाला दिया है। सेस्टेट ने अपने आदेश में यह पाया है कि -
15. जब समीक्षा के आवेदकों ने समीक्षा की संबद्ध अवधि के दौरान न ही बेचा है और न ही कोई निर्यात किया है, तो यह स्वभाविक है कि वे गैर-प्रवर्तक थे और वे नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर की समीक्षा का दावा करने के पात्र नहीं थे। चूंकि उत्पादक-निर्यातक ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया है और निर्यातकों ने न्यू शिपर समीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने से पहले भारत को कोई निर्यात नहीं किया है, वे नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा शुरू करवाने के वास्ते आवेदन करने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए न्यू शिपर समीक्षा शुरू करना नियमावली के नियम 22 के विपरीत है। इसलिए समीक्षा को शुरू करने के लिए उन्हें ऐसा अवैध और गैर-अवस्थापक घोषित किया गया था, जो कि अंतिम जांच परिणाम को संदूषित और अधिसूचना को प्रतिवादित करते हैं। इसलिए प्रतिवादित अधिसूचना और अंतिम जांच परिणामों को सुस्थिर नहीं बनाए रखा जा सकता है और उसे एतद्वारा रद्द किया जाता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।
- (द) आवेदक *एच एंड आर जोनसन (2007)* के मामले में वास्तविक स्थिति और संबद्ध समीक्षा में वास्तविक स्थिति के बीच की भिन्नता दिखलाता है। सेस्टेट के निर्णय निम्नोक्त कारणों से आवेदक पर लागू नहीं होते हैं:-
- (1) *एच एंड आर जोनसन (2007)* के मामले में न्यू शिपर ने न्यू शिपर समीक्षा का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले उत्पादन अथवा भारत को निर्यात करना शुरू नहीं किया था। आवेदक ने न्यू शिपर समीक्षा का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले उत्पादन करना और पर्याप्त मात्रा में भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया था।
 - (2) *एच एंड आर जोनसन (2007)* के मामले में न्यू शिपर को नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए अयोग्य पाया गया था।
 - (3) *एच एंड आर जोनसन (2007)* के मामले में समीक्षा की समस्त अवधि भावी थी। इस संबद्ध समीक्षा में जांच की अवधि आंशिक भावी और आंशिक पूर्वव्यापी थी।
- (ध) आवेदक ने *एच और आर जोनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 2008 (232) ई.एल.टी. 390* के मामले पर विश्वास किया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि न्यू शिपर समीक्षा प्रथम बार के निर्यातक के मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव से शुरू नहीं की जा सकती है।
- (न) आवेदक का संयंत्र नया है और यह पुराना संयंत्र नहीं है। वर्तमान मामला आवेदक को बेचे गए क्यूवाईजीएमएमसी के पुराने संयंत्र से अपवंचना करने का नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) वर्तमान न्यू शिपर समीक्षा विधि में निकृष्ट है। न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से पहले नियम 22 की अनिवार्य आवश्यकताएं और पूर्व शर्त को पूरा नहीं किया गया है। न्यू शिपर समीक्षा शुरू करवाने के लिए निर्यातक और उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन-पत्र निम्नोक्त कारणों से विकट रूप से अपर्याप्त और अधिप्रमाणित नहीं है:-
- (1) आवेदक ने मूल जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात की कमी को सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।
 - (2) आवेदक से संबंधित किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा और सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके द्वारा मूल जांच की अवधि के दौरान "कोई निर्यात नहीं होने" की शर्त पूरी की गई है।
 - (3) आवेदक ने संबंध होने के बारे में अपूर्ण घोषणा की है और वह मेसर्स क्विनुआंगडाओ याहुआ ग्लास मशीन मेन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड (क्यूवाईजीएमएमसी) के साथ अपने संबंध की प्रकृति और सीमा को सिद्ध करने/स्पष्ट करने में विफल रहा है।
 - (4) इस संबंध में कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्या उत्पादक द्वारा नया संयंत्र अथवा पुराना संयंत्र अधिग्रहीत किया गया है।
- (ख) आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह कुछ दस्तावेजों पर गोपनीयता के दावे के कारणों को बताने में विफल रहा है तथा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि वह संक्षिप्त विवरण के लिए क्यों संवेदनशील नहीं है। आवेदक ने कुछ दस्तावेजों और क्यूवाईजीएमएमसी के साथ संविदा के अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत नहीं किए हैं। आवेदक ने सार्थक अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ग) नियम 22 के अंतर्गत आवेदक को यह दर्शाना आवश्यक होता है कि वह ऐसी सभी देशों के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है जिनके उत्पाद पर शुल्क लागू होता था।
- (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेरलाईट इंडस्ट्रीज के मामले में नियम 7 की विधि को अत्यंत स्पष्ट कर दिया था और उसके बाद माननीय न्यायाधिकरण ने भी उसको स्पष्ट कर दिया था। माननीय न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक सूचना को मात्र इस कारणवश गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए कि जांच की कार्रवाई के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
- (ङ) आवेदक ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 की पूर्व-शर्तों को पूरा नहीं किया है। न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए नियम 22 के अंतर्गत जांच शुरू करने की पूर्व-शर्त के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उचित और पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। नियम 22 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि निर्यातक देश में आवेदक द्वारा जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए जाने चाहिए और वह निर्यातक देश के ऐसे किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं होना चाहिए जिन पर संबंधित उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होता है। "निर्यातक देश" जांच अधीन देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे सभी देश भी शामिल हैं, जिन पर विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है।
- (च) आवेदक ने शुल्कों की अपवंचना करने के लिए चीन में स्थित क्यूवाईजीएमएमसी नामक अपनी कंपनी के बारे में झूठी घोषणा की है। क्यूवाईजीएमएमसी ने चीन में अनेक प्लोट ग्लास लाईनों में निवेश किया हुआ है और उसमें आवेदक भी एक शेयरधारक है तथा दिनांक 08.09.2015 की अधिसूचना संख्या 47/2015-सीमा-शुल्क (एडीडी) के अनुसार वह पाटन-रोधी शुल्क के अध्यधीन है। आवेदक ने इस तथ्य को रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है।

- (छ) यह निश्चित है कि यदि ऐसा आरोपित प्रकटन जिसे बाद में आवेदक द्वारा अपने पत्रों, लिखित निवेदनों और चीन की शेयरधारक कंपनी के बारे में उत्तर दे कर किया गया है, जांच शुरू करने से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में ला दिया जाता, तो इस मामले की शुरुआत ही नहीं होती। वास्तविक तथ्यों को दबाने और आवेदक के आचरण से जांच की अवांछनीय शुरुआत करवाने की उसकी दुर्भावना का स्पष्ट पता चलता है।
- (ज) जांच की अवधि 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक के 9 महीनों के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि विवेकाधीन है। 9 महीनों की ऐस अल्प अवधि का निर्धारण निर्दिष्ट प्राधिकारी के व्यापारिक सूचना के विपरीत है, जिसमें यह विनिश्चित किया गया है कि जांच की न्यूनतम अवधि 12 महीनों की होगी। इसके अतिरिक्त चयनित जांच अवधि भावी है। नियम 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच की ऐसी भावी अवधि निर्धारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में विधि का स्पष्ट रूप से निर्धारण, एच एंड आर जोनसन के मामले में कर दिया गया है, जिसमें न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि भावी अवधि का चयन करना अवांछनीय है और यह पाटन-रोधी शुल्क लगाने की समग्र योजना और प्रयोजन को विकृत कर देगा, जो कि पाटन-रोधी शुल्क से संरक्षण प्राप्त घरेलू उद्योग के लिए विकट हानिकारक होगा।
- (झ) निर्यातक ने कोई औचित्यपूर्ण कारण बताए बिना अत्यधिक गोपनीयता का दावा करते हुए उत्तर का उचित अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा है कि उसने ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि वह उस पर टिप्पणी देने अथवा अपने निवेदनों में अपर्याप्तता प्रकट करने की स्थिति में नहीं हैं।
- (ञ) यह निवेदन किया जाता है कि न्यू शिपर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में तथा प्रस्तुत किए गए अपने उत्तरों में नकदी के बदले शेयरों का आबंटन किए जाने की असंगति के बारे स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण सूचना को प्रस्तुत नहीं करने से उसके असहयोग और प्राधिकारी को भ्रमित करने तथा जांच में अवरोध उत्पन्न करने के उसके इरादे का स्पष्ट पता चलता है। इसलिए न्यू शिपर के उत्तर को विधि की आवश्यकता को पूरा नहीं करने और सूचना का प्रकटन नहीं किए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (ट) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे चीन की कंपनी के साथ मेसर्ज तारीक फ्लोट ग्लास लिमिटेड (पाकिस्तान) के संबंध होने का विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान से न्यू शिपर का चीन में उत्पादक/निर्यातक और चीन की कंपनी के साथ संबंध है, इसलिए न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) को समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है।
- (ठ) एचएंडआर जोनसन इंडिया लिमिटेड बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, 2005 के मामले में तथा कम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल) के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिणामों में यह बताया गया है कि प्राधिकारी जांच शुरू करने से पहले और जांच की कार्रवाई के दौरान साक्ष्य के संबंध में सूचना एकत्र कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग पुनः निवेदन करता है कि प्राधिकारी को मेसर्ज तारीक फ्लोट ग्लास लिमिटेड और याहुआ ग्रुप के बीच स्थापित संबंध की प्रकृति और ढांचे का पता लगाने के लिए याहुआ ग्लास ग्रुप कार्पोरेशन, चीन की जांच करनी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के निम्नोक्त प्रावधानों को ध्यान में रख कर न्यू शिपर समीक्षा की शुरू की है:-

"नियम 22 :

- (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक

समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

- (2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"

13. नियम 22 में ऐसी परिस्थितियां विनिश्चित हैं जिनमें विशिष्ट पृथक मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की जा सकती है। संबद्ध निर्यातक देश से किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में विशिष्ट पृथक मार्जिन का निर्धारण, निम्नोक्त दो शर्तों को पूरा करने पर किया जा सकता है:-

- (क) यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के निर्यात नहीं किए हैं और
(ख) यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने यह दर्शाता है कि वह निर्यातक देश में ऐसे किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिनके संबंधित उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगता है।

14. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि नियम 22 का अभिप्राय किसी ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए विशिष्ट पृथक मार्जिन का निर्धारण करना है, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। चूंकि मूल जांच की जांच अवधि के दौरान ऐसे उत्पादक/निर्यातक ने भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं, इसलिए प्राधिकारी मूल जांच के दौरान उसके निर्यातों के संबंध में विशिष्ट पृथक मार्जिन का निर्धारण नहीं कर सकते थे। इसलिए न्यू शिपर समीक्षा के प्रावधान का उद्देश्य इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इन निर्यातकों को मूल जांच के दौरान अवशिष्ट विशिष्ट पृथक मार्जिन स्वीकृत किया गया है, ऐसे उत्पादक/निर्यातक को विशिष्ट पृथक मार्जिन का दावा करने का अवसर प्रदान करना है।

15. वर्तमान मामले में मेसर्स तारीक ग्लॉस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान ने प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन की मांग की है और उनसे न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है।

16. नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने की मूल आवश्यकताएं यह हैं: (क) संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लागू होता है और (ख) विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन की मांग करने वाले निर्यातकों अथवा उत्पादकों द्वारा मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए गए होने चाहिए और उन्हें यह प्रमाणित करना चाहिए कि वे ऐसे निर्यातक देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिनकी संबद्ध वस्तुओं पर पाटन शुल्क लगता है। न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने वाले आवेदक को आवेदन-पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह नियम 22 में निर्धारित उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है और आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि उसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं और वह ऐसे निर्यातक देश में किसी भी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिनकी संबद्ध वस्तुओं पर पाटन शुल्क लगता है। प्राधिकारी को न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से पहले कोई व्यापक जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें प्रथम दृष्टया इस तथ्य से संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि नियम 22 में उल्लिखित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जब तक आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरणों के विपरीत कोई वास्तविक प्रतिकूल साक्ष्य का पता नहीं चलता है, तब तक प्राधिकारी न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से मनाही नहीं

कर सकते हैं। वर्तमान मामले में न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने की तारीख से रिकार्ड में ऐसे किसी वास्तविक तथ्य का पता नहीं चलता है कि मेसर्स तारीक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा दिए गए विवरण सही नहीं हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने से पहले प्राधिकारी के पास संतोष जनक प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं थे और तदनुसार न्यू शिपर समीक्षा शुरू करना यथोचित है।

17. न्यू शिपर के रूप में आवेदक की अर्हता से संबंधित दावों की यह जानने के लिए जांच की गई है कि क्या कंपनी ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। आवेदक से अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि आवेदक अथवा उससे संबंधित कंपनी ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं। आवेदक ने यह निवेदन करते हुए अधिप्रमाणन प्रस्तुत किया है कि -

- (क) आवेदक ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए हैं।
- (ख) आवेदक पाकिस्तान में ऐसी किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं।
- (ग) आवेदक सऊदी अरब, यूएई, चीन, इंडोनेशिया और ईरान में ऐसी किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिसने इन देशों के खिलाफ मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं।
- (घ) आवेदक से संबंधित कंपनियां, संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने में नहीं लगी हुई थीं।
- (ङ) आवेदक से संबंधित कंपनियां, पाकिस्तान में ऐसी किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं।
- (च) आवेदक से संबंधित कंपनियां, सऊदी अरब, यूएई, चीन, इंडोनेशिया और ईरान में ऐसी किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क लगता है।

प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदनों पर विचार किया है, लेकिन न्यू शिपर के रूप में आवेदक के दावे के खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई है।

18. आवेदक के चीन की कंपनी, मेसर्स क्विनुआंगडाओ याहुआ ग्लास मशीन मेन्युफैक्चरर कंपनी लिमिटेड (क्यूवाईजीएमएमसी) के साथ संबंध होने के मुद्दे के बारे में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-

(क) विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"9.5 यदि कोई उत्पाद आयातक सदस्य में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हो तो प्राधिकारी जाँच के अधीन निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तत्काल समीक्षा करेंगे जिसने जाँच अवधि के दौरान आयातक सदस्य को उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह दर्शा सकता हो कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। ऐसी कोई समीक्षा आयातक सदस्य में सामान्य शुल्क निर्धारण और समीक्षा कार्यवाही की तुलना में सक्रिय आधार पर शुरू की जाएगी और चलाई जाएगी। समीक्षा के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते और/या यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो पाटनरोधी शुल्क को समीक्षा की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सके।"

(ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 9.5 के अंतर्गत आवश्यकता यह सिद्ध करने की है कि आवेदक (जो कि पाकिस्तान में अवस्थित उत्पादक-निर्यातक है) ने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध उत्पाद के निर्यात नहीं किए हैं और वह पाकिस्तान में ऐसे किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित

नहीं है, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं तथा जिसके संबद्ध उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगते हैं। आवेदक ने स्पष्ट रूप से इस आवश्यकता को पूरा किया है कि वह पाकिस्तान में ऐसे किसी भी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं है, जिसने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं तथा जिसके संबद्ध उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगते हैं।

- (ग) प्राधिकारी अपवंचना की संभावना के संबंध में घरेलू उत्पादकों की चिंताओं को नोट करते हैं और इसलिए उन्होंने आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी के बीच संबंध होने के बारे में जांच की है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी के बीच संबंध पूर्णतया संविदात्मक हैं और क्यूवाईजीएमएमसी के शेयरों का स्वामित्व केवल संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति करने के लिए आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी के बीच की गई संविदा के प्रासंगिक है। आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी के बीच संबंध, सेवा प्रदायक और सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में है।
- (घ) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में आवेदक से संबंधित कंपनियों की सूची निहित है। आगे यह भी नोट किया गया है कि सूचीबद्ध संबंधित कंपनियों में क्यूवाईजीएमएमसी का उल्लेख नहीं है।
- (ङ) घरेलू उत्पादकों ने आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी नामक चीन की कंपनी के बीच कोई "सार्थक" संबंध होने की संपुष्टि नहीं की है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि नियम 22 के प्रयोजनार्थ "संबंध" को सिद्ध करने के लिए संविदात्मक संबंध होना पर्याप्त नहीं है।
- (च) इसके अतिरिक्त क्यूवाईजीएमएमसी की शेयरधारिता 5% से भी कम है, जो कि हित के नियंत्रण को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है। क्यूवाईजीएमएमसी द्वारा शेयरधारिता के आधार पर आवेदक के निदेशक मंडल में किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है। आवेदक और क्यूवाईजीएमएमसी किसी भी प्रकार से सामान्य प्रबंधन और नियंत्रण में नहीं हैं अथवा आवेदक के विनिर्माण अथवा व्यवसाय की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से क्यूवाईजीएमएमसी पर निर्भर नहीं है। आवेदक का कोई भी उत्पाद क्यूवाईजीएमएमसी को बेचा अथवा अंतरित नहीं किया जाता है।
- (छ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत आवेदक क्यूवाईजीएमएमसी से संबंधित नहीं है।

19. जांच के दौरान प्राधिकारी ने आवेदक के पाकिस्तान में ऐसे किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक के साथ संबंधित होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं पाया है, जिस पर पाटन-रोधी शुल्क लगता है और न ही इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की गई है, जो कि विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि आवेदक ऐसे किसी भी देश में अवस्थित किसी भी निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं है, जिस पर शुल्क लागू होता है।

20. जांच की अवधि के संबंध में निवेदन है कि प्राधिकारी द्वारा 12 महीनों से कम अवधि का निर्धारण करना उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। न्यू शिपर के मामले में जांच की अवधि के रूप में अल्प अवधि पर विचार करना असमान्य नहीं है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चयनित अवधि आंशिक रूप से पूर्वव्यापी और आंशिक रूप से भावी है। प्राधिकारी जांच की पूर्वव्यापी अवधि का चयन करने के प्रति घरेलू उद्योग की चिंताओं को नोट करते हैं और वास्तव में ये चिंताएं बहुत वैध हैं। तथापि, वर्तमान मामले की तथ्यपरक स्थिति, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लेख किया गया है, एचएंडआर जोनसन (2007) के मामले की वास्तविक स्थिति से विशेष रूप से

भिन्न है। एचएंडआर जोनसन (2007) के मामले में सेस्टेट ने निम्नलिखित आधार पर न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत करने की अमान्यता को स्पष्ट रूप से नोट किया है:-

- (1) न्यू शिपर ने न्यू शिपर समीक्षा का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के समय अपना उत्पादन और भारत में निर्यात करना शुरू नहीं किया था।
- (2) नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू करने के लिए न्यू शिपर को अयोग्य पाया गया था।
- (3) समीक्षा की समस्त अवधि भावी थी।

21. संबद्ध समीक्षा शुरू करते समय प्राधिकारी सेस्टेट द्वारा एचएंडआर जोनसन (2007) के मामले में यथा निर्धारित इन आवश्यकताओं के प्रति जागरूक थे और उन्होंने संबद्ध समीक्षा शुरू करने से पहले इन मुद्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदक ने न्यू शिपर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पहले अपना उत्पादन करना और भारत में पर्याप्त मात्रा में निर्यात करना शुरू कर दिया था। चयनित अवधि आंशिक रूप से पूर्वव्यापी और आंशिक रूप से भावी है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी नियमावली के नियम 22 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि न्यू शिपर समीक्षा में जांच की समस्त अवधि पूर्वव्यापी नहीं हो सकती है। इस प्रकार जांच की अवधि का चयन यथोचित है।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने मूल जांच की जांच अवधि के बाद से ही संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक का मुख्य व्यवसाय संबद्ध वस्तुओं सहित सभी प्रकार के शीशे के उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करने का है। आवेदक ने अपनी भट्टी को सुलगाना और संबद्ध वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया था। आवेदक द्वारा तैयार उत्पाद को घरेलू बाजार में असंबंधित कंपनियों के साथ-साथ निर्यात बाजार में सीधे बेचा जाता है। आवेदक कंपनी के केवल दो मुख्य शेयरधारक/स्वामी हैं, जो कि विशेष रूप से व्यक्तिगत हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक की पाकिस्तान में तीन संबद्ध कंपनियां हैं और इन तीनों संबद्ध कंपनियों ने यह प्रमाणित किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं कर रही हैं और वे पाकिस्तान, सऊदी अरब अथवा यूएई में ऐसे उत्पादकों और निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं, जिन्होंने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए हैं।

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा किसी पक्षकार द्वारा जांच के दौरान गोपनीय आधार पर प्रदत्त किसी अन्य सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने के उपरांत गोपनीय ही माना जाएगा और ऐसी किसी सूचना का प्रकटन ऐसे सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी दूसरे पक्षकार को नहीं किया जाएगा।

(2) गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदाता किसी पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव न हो तो ऐसा पक्षकार इस आशय के कारणों का एक विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है कि उसका सारांश प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसके प्रकटन का प्राधिकार प्रदान करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को

स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की कार्य-प्रणाली

सामान्य मूल्य

26. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए सामान्य कार्य-प्रणाली

26. प्राधिकारी द्वारा पहले यह निर्धारित किया गया था कि क्या आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तुओं की कुल घरेलू बिक्रियां, भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों की तुलना करने की प्रतिनिधिक हैं।

27. उसके बाद इसकी जांच की गई थी कि क्या उनकी बिक्रियां, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 2 के अनुसार सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान की गई हैं। उत्पादक और निर्यातक ने गृह बाजार में की गई अपनी बिक्रियों के कारोबार-वार व्यौरे प्रस्तुत किए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा गृह बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उक्त सूचना पर विश्वास किया गया है।

28. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए संबंधित उत्पाद के उत्पादन की लागत की जांच, आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना के संदर्भ में की गई थी और उसकी तुलना घरेलू बिक्री कीमत के साथ की गई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या घरेलू बिक्रियां सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान की गई हैं अथवा नहीं। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में सभी कारोबार पर विचार किया है, जिनमें

लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से अधिक हैं और ऐसे मामले में जहां लाभप्रद कारोबार 50% से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया गया है।

29. निबल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है ताकि न्यू शिपर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना की परिशुद्धता सत्यापित की जा सके। आगे यह भी नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन का आकलन करने के लिए उसी स्तर पर तुलना की गई थी।

आवेदक के लिए सामान्य मूल्य

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं जिनमें जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों और उनके उत्पादन की लागत के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं। घरेलू बाजार में सभी बिक्रियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र ग्राहकों को की गई हैं। आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं की *** घरेलू बिक्रियां होने और उनका सकल बीजक मूल्य *** होने के बारे में सूचित किया है। भारत के निर्यातों के साथ तुलना करने से ऐसा पता चलता है कि घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हुई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सभी घरेलू बिक्रियों के कारोबार पर विचार किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया का संचालन किया था ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों के कारोबार का निर्धारण किया जा सके और साथ ही यह भी निर्धारित किया जा सके कि क्या लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से अधिक हैं अथवा नहीं। चूंकि लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से कम थे, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जित करने वाले कारोबार पर ही विचार किया है।

31. आवेदक ने छूट, कमीशन, पैकिंग लागत और ऋण लागत पर समायोजन किए जाने का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए अनुसार ऐसा समायोजन करने की स्वीकृति दी है और आवेदक के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य, नीचे दी गई पाटन मार्जिन की तालिका में निर्दिष्ट किया गया है।

निर्यात कीमत

32. निर्यातक की प्रश्नावली के अनुसार जांच अवधि के दौरान आवेदक ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन निर्यात किए थे, जिनका सकल बीजक मूल्य *** था। ये निर्यात सीधे भारत में स्वतंत्र ग्राहकों को किए गए थे। आवेदक ने अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन हैंडलिंग व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए अनुसार ऐसा समायोजन करने की स्वीकृति दी है और आवेदक के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं की निबल निर्यात कीमत की तुलना, सत्यापित आंकड़ों/सूचना के आधार पर पैकिंग रहित क्लियर फ्लोट ग्लास के लिए आकलित सामान्य मूल्य के साथ की गई है और उसकी आगे संपुष्टि, डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के साथ की गई है। इसके ब्यौरे नीचे दी गई पाटन मार्जिन की तालिका में दिए गए हैं।

पाटन मार्जिन

33. उपरोक्त यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए जांच अवधि के दौरान आवेदक के लिए निर्धारित किया गया विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

देश	निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमरीकी डालर)	निबल निर्यात कीमत (अमरीकी डालर)	पाटन मार्जिन (अमरीकी डालर)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन सीमा
पाकिस्तान	मेसर्ज तारीक ग्लॉस	***	***		***	5-15

	इंडस्ट्रीज लिमिटेड					
--	--------------------	--	--	--	--	--

प्रकटन पर टिप्पणियां**आवेदक द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात की गई टिप्पणियां**

34. आवेदक जांच की कार्रवाई के दौरान किए गए निवेदनों को स्वीकार करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि प्रकटन में यथा प्रस्तुत विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो प्राधिकारी को एक अवसर देते हुए आवेदक के लिए व्यक्तिगत अनिवार्य सुनवाई स्वीकृत करनी चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात की गई टिप्पणियां

35. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

- (क) इस मामले में जांच की शुरुआत करना स्वतः न्यायाधिकार के बिना है क्योंकि आवेदक उद्योग ने जांच शुरू करवाने के लिए पूर्णतः चालाकी करने का आश्रय लिया है।
- (ख) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से बार-बार यह अनुरोध किया है कि वे जांच अवधि के लिए सूचित की गई निर्यात कीमत को सत्यापित करें और उसकी वास्तविकता की जांच करें क्योंकि 13 मिली मीटर के उत्पादों का कम कीमत पर निर्यात किया जाता है और वे कृपया मेसर्स तारीक ग्लास द्वारा उसी अवधि के दौरान अन्य देशों को पेश की गई कीमतों की जांच करें।
- (ग) समय बीत जाने के कारण वर्तमान मामले में प्राधिकारी का कोई न्यायिक अधिकार नहीं है क्योंकि नियम 17 के अनुसार जांच में निष्कर्ष देने के लिए प्राधिकारी को उपलब्ध अधिकतम समय-अवधि 18 महीनों की होती है और वह समाप्त हो गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई अधिकतर टिप्पणियां/निवेदन पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं, जिनकी पहले से ही उचित जांच कर ली गई है और उनका निदान प्रकटन विवरण में अथवा वर्तमान जांच परिणाम के संबद्ध पैराओं में कर दिया गया है और इसलिए संक्षेपण को ध्यान में रखते हुए उनको यहां दोहराया नहीं जाता है। तथापि, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का निदान करना उचित समझते हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- (क) 13 मिली मीटर चौड़ाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की कीमत के बारे में घरेलू उद्योग के निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में 13 मिली मीटर चौड़ाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की कीमत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वह विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मोटाई के उत्पादों की कीमतों का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है तथा एक विशिष्ट मोटाई के उत्पाद की कीमत की तुलना, किसी अन्य विशिष्ट मोटाई के उत्पाद के साथ करना सही नहीं है। घरेलू उद्योग का ऐसा दावा कोई महत्ता नहीं रखता है क्योंकि वह यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा है कि तारीक ग्लास द्वारा आपूर्ति किए गए 13 मिली मीटर चौड़ाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की कीमत, अन्य देशों से आयात किए गए 13 मिली मीटर चौड़ाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की कीमत की तुलना में कम है। इसलिए संबद्ध वस्तुओं की कीमतें, आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए 13 मिली मीटर चौड़ाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास की कीमतों के साथ सह-संबंध स्थापित करने का कोई उचित आधार नहीं है।
- (ख) प्राधिकारी ने भारत को निर्यातों के लिए डीजीसीआईएंडएस से आवेदक द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत कर वास्तविकता की जांच की है और साथ ही उसकी तुलना, उसी अवधि में तारीक ग्लास द्वारा अन्य देशों को पेश की गई कीमत के साथ भी की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत और अन्य देशों की निर्यात कीमत के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। तदनुसार घरेलू उद्योग के इस तर्क का कोई महत्व नहीं है।

- (ग) न्यू शिपर समीक्षा इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत करने के संबंध में, प्राधिकरण यह बताता है कि पाटन-रोधी नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यू शिपर रिव्यू जांच के अंतिम निष्कर्ष पूरे किए गए हैं।

प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष और सिफारिशें

37. उपरोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -
- (1) जांच अवधि के दौरान मेसर्ज तारीक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास की निर्यात कीमत, उसके अपने सामान्य मूल्य से कम है।
 - (2) इसलिए प्राधिकारी, मेसर्ज तारीक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान द्वारा उत्पादित और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 20 के अंतर्गत आने वाले 4 मि.मी. से 12 मि.मी. (दोनों सम्मिलित) के रेंज की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास, जिनकी मामूली मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है, क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों पर *** अमरीकी डालर प्रति मीटर टन पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
38. अधिनियम के अनुसार इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2017

(New Shipper Review)

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of the Anti-Dumping Rules for determination of individual dumping margin for the purpose of imposition of anti-dumping duty on dumped imports of Clear Float Glass, originating in or exported from Pakistan, in respect of M/s. Tariq Glass Industries Ltd. (producer and exporter).

F. No. 15/16/2015-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as AD Rules);

A. BACKGROUND

2. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) initiated anti-dumping duty investigation concerning “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000” (hereinafter referred to as “subject goods”) originating in or exported from Saudi Arabia, UAE and Pakistan vide initiation Notification No F.No.14/25/2012-DGAD dated 11th April 2013. The Authority vide final findings dated 10th October 2014 recommended an anti-dumping duty for all exporters/producers from Pakistan, Saudi Arabia and UAE at the rates prescribed in the said findings. The recommendation of the Designated Authority was accepted by Central Government and antidumping duty was levied vide Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December 2014.
3. M/s Tariq Glass Industries Ltd (hereinafter referred to as “New Shipper” or “Applicant”) filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with Rule 22 of the AD Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) in respect of the definitive anti-dumping duty

imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December 2014, concerning imports of the subject goods, originating in or exported from Pakistan.

4. The Act and the AD Rules made there under require the Authority to undertake a New Shipper Review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country and that the applicant is not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the antidumping duty. The applicant claimed that they are not related to any of the exporters/producers in Pakistan or other subject countries against who anti-dumping measures are in force with regard to the product concerned. Furthermore, they claimed that they have not exported the product concerned during the period of investigation of the original investigation.
5. The Authority prima facie examined the information submitted by the applicant and at the stage of initiation of the investigation, found it sufficient to justify the initiation of a new shipper review investigation in accordance with the provisions of Rule 22 of the AD Rules. The Authority accordingly initiated the New Shipper Review under Rule 22 of the AD Rules vide Notification F. No. 15/16/2015-DGAD dated 23rd September, 2015. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st July, 2015 to 31st March, 2016 (9 months).
6. Having initiated the subject NSR investigation, the Authority recommended provisional assessment on all exports of subject goods made by M/s Tariq Glass Industries Ltd., till this review is completed in accordance with Rule 22 of the Rules supra and having regard to Customs Notification No. 48/2014- Customs (ADD) dated 11th December 2014.
7. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Tariq Glass Industries Ltd. till completion of the subject NSR investigation vide Notification No. 53/2015-Customs (ADD) dated 30th October, 2015.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - a. The Authority issued a public notice dated 23rd September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - b. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the NSR applicant along with a copy of the exporter's questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - c. The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the Pakistan High Commission in New Delhi.
 - d. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - e. In response to the initiation notification, response in the form of Exporters Questionnaire was filed by M/s Tariq Glass Industries Ltd.
 - f. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this findings.
 - g. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
 - h. The Authority held Oral Hearings on 17th August and 2nd November 2016 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from interested parties appropriately.
 - i. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. The data submitted by the Applicant was examined and back-up documents were called for, wherever required.
 - j. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for the findings were disclosed to known interested parties on 27th March 2017 and comments received on the same have been considered in the Final Findings.
 - k. *** in the findings represent information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the AD Rules.

1. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential.

C. Product Under Consideration

9. The present investigation relates to exports of Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900: 2000. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the scope of the product under consideration under the investigation.

D. Views of the Applicant / New Shipper, M/s Tariq Glass Industries Ltd (Producer cum Exporter)

10. The views of the Applicant have been summarized below:
 - a. The Applicant did not export the PUC to India during the period of investigation of the original investigation, i.e., 1st October 2011-31st December, 2012.
 - b. The Applicant started production of PUC in April, 2013 and began exporting the PUC to India with effect from 12th July, 2013, subsequent to period of investigation of the original investigation.
 - c. The Applicant has no related company engaged in the production of the PUC. None of the related companies of the Applicant exported the PUC to India during the period of investigation of the original investigation, i.e., 1st October 2011-31st December, 2012.
 - d. The Applicant is not related to any of the exporters or producers in Pakistan, Saudi Arabia and UAE. The Applicant is also not related to any of the exporters or producers in China PR.
 - e. The Applicant participated before the Designated Authority in the original investigation and filed injury submissions and comments on the Petition. However, the Applicant did not file questionnaire response at the time of the Original investigation because it had no exports to India during the period of investigation of the original investigation.
 - f. The Applicant Company has not exported PUC to India during the period of investigation of the original investigation and is not related to any other entity that had exported PUC to India during the period of investigation of the original investigation. The Applicant also certified that it is not related to any entity in any country on which anti-dumping duty on the subject goods is applicable. Thus, the Applicant satisfied both the requirements of Rule 22 of the AD Rules and was eligible for the initiation of the New Shipper Review and the determination of an individual rate of duty.
 - g. The Applicant did not claim excessive confidentiality. All the documents upon which confidentiality was claimed contain business confidential information and are not available in the public domain and did not impact or prejudice the Domestic Producers. The Contract between QYGMMC (M/s. Qinquangdao Yaohua Glass Machine Manufacture Company Ltd) and the Applicant is subject to a confidentiality clause therein and thus, was not shared with the Domestic Producers.
 - h. The Applicant procured a new plant for production of Float Glass from QYGMMC and part payment for procurement, erection and commissioning was made through issue of shares for better management of cash flows. The Applicant opted to issue 41, 58,000 shares for this purpose. Out of this, 31, 18,500 shares were issued to QYGMMC which amounts to 4.25% of the total shares of the Company and 10, 39,500 shares were issued to Global Link Glass Company, another service provider. QYGMMC and Global Link Glass Company are not related to each other. The issue of shares pursuant to the contract with QYGMMC was also duly disclosed in the Applicant's Financial Statements in Note 13 for the year ended June 30, 2013 and June 30, 2014. Out of these 31, 18,500 shares, QYGMMC subsequently disposed of 5, 50,000 shares in the year 2015 and consequently the shareholding of QYGMMC has come down to 3.5% during the POI for the present new shipper investigation. The 3.5% of shares so held by QYGMMC, directly or indirectly, were merely payment, and do not create any "relation" between the two companies. The shareholding of QYGMMC was not a direct investment by it rather the shares were issued to it against partial payment for plant and machinery supplied by it. Based on the fact that 3.5% of the Applicant's shares are held by QYGMMC, the DI attempts to raise the argument that the Applicant is "controlled" by them or that the two are "related". This is not the case and the conditions for establishing "relation" under Rule 2(b), the only comparable standard under the Rules, are not even remotely considered by the DI.

- i. QYGMMC does not have any representation on the Board of Directors of the Applicant Company, has no direct or indirect control which gives it any influence over the Applicant or which gives it any right to direct any of the Applicant's operating decisions. QYGMMC has no family relation with the Applicant. The Applicant and QYGMMC are not under any common management or control and the manufacturing process or business of the Applicant is not in any way dependent on QYGMMC. This fact can be verified from the annual report of the Applicant. No products of the Applicant are sold or transferred to QYGMMC.
- j. The Applicant is not related to Yaohua Glass Group Corporation, as alleged by the Domestic Producers.
- k. The Domestic Producers cannot question the Applicant's certification regarding lack of exports at this stage when they did not question it at the time of the original investigation. The Domestic Producers are estopped by their waiver in this regard. The Applicant relied on the Supreme Court decision in *Ferro Alloys Corpn. Ltd. & Anr. vs. Union of India & Ors*, (1999) 4 SCC 149, wherein the Supreme Court rejected the argument that an appellant could challenge a part of a departmental order that it had previously supported without qualification by virtue of estoppel, waiver and acquiescence
- l. The Applicant cited the decision of the CESTAT in *H&R Johnson* (2005) to establish that the condition under Rule 22 of the AD Rules could be satisfied at any point of the Review proceeding, and the condition was not necessarily required to be satisfied prior to initiation.
- m. The Domestic Producers are misguided in their understanding that "exporting country" under Article 9.5 of the WTO AD Agreement refers to *all* exporting countries on whom anti-dumping duty is applicable and not just Pakistan where the applicant is based. The Applicant has submitted that acceptance of such a premise would lead to many practical complications in the conduct of the New Shipper Reviews, especially for MNCs and where multiple period of investigations are involved
- n. The Domestic Producers are misguided in their understanding of the term "related" as it appears in Rule 22 of the AD Rules. The Applicant is not 'related' to QYGMMC. The relationship between QYGMMC and the Applicant is purely contractual and the subject contract is available with the Designated Authority for examination. The Applicant is not "related" to QYGMMC by any standard available under AD law or any other laws.
- o. The Domestic Producers have misunderstood the scope of "subject to anti-dumping duty" under Rule 22. The Applicant presses that, under Rule 22, "subject to anti-dumping duty" refers only to those entities which are subject to *individual dumping rate* and not those subject to *residual rates*. In this regard, the Applicant relies on *H&R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority*, 2007 (218) E.L.T. 273 (paragraph 5).
- p. The selected period of investigation is not arbitrary as stated by the Domestic Producers. Annexure I, para. 2(i) to the AD Rules provides that the period of investigation to determine the normal value, the export price and the dumping margin should be "a reasonable period of time (not less than six months)".
- q. The Domestic Producers claim that selection of a prospective period of investigation for the subject new shipper review is arbitrary and that the initiation of the subject review is bad in law. In this regard the Domestic producers cite *H&R Johnson India Ltd. vs. Designated Authority* 2007 (218) E.L.T. 273 (Tri. - Del.). The CESTAT in this order, found that:

15. When the review applicants had neither exported nor sold for export during the relevant period of review, they were obvious non-starters and were not eligible to claim new shipper review under Rule 22. Since the producer-applicant had, admittedly, not produced the subject goods before making the application for new shipper review and the exporters did not make any export to India prior to their new shipper review applications, (they were not qualified for applying for initiation of new shipper review under Rule 22. The initiation of review was, therefore, contrary to Rule 22 of the rules. The review proceedings are, therefore, declared illegal and non est, vitiating the impugned final findings and the impugned notification. The impugned notification and final findings cannot, therefore, be sustained and are hereby set aside. The appeal is, accordingly, allowed.

- r. The Applicant distinguishes the factual situation in the subject review with the factual situation in *H&R Johnson* (2007) case. The findings of the CESTAT are not applicable in the Applicant's case because:
 - i. In the *H&R Johnson* (2007) case, the new shippers had not begun production or exportation to India at the time of filing the new shipper review application. The Applicant has begun

- production and export to India in substantial quantities before filing the new shipper review application.
- ii. In the *H&R Johnson* (2007) case, the new shippers were found to be ineligible for initiating a new shipper review under Rule 22.
 - iii. In the *H&R Johnson* (2007) case, the entire period of review was prospective. The subject review herein consists of a period of investigation that is part prospective and part retrospective.
 - s. The Applicant also relies on *H and R Johnson (India) Limited v. Union of India & Ors.*, 2008 (232) E.L.T. 390, wherein the Delhi High Court stated that “*the initiation of a new shipper review cannot be with retrospective effect in the case of a first time exporter*”.
 - t. The Applicant’s plant is a new plant, not an old plant. The instant case is not one of circumvention by way of old plant of QYGMMC being sold off to the Applicant.

E. Views of the Domestic Producers

11. The submissions made by the Domestic Industry and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. The initiation of the present New Shipper Review is bad in law. The mandatory requirements and pre-conditions of Rule 22 have not been satisfied prior to initiation of new shipper review. The application filed by the exporter and the producer for the initiation of new shipper review is grossly inadequate and unsubstantiated in view of the following;
 - i. The Applicant has supplied no data to establish the lack of exports to India during the period of original investigation;
 - ii. No data and information has been filed by any of the related party of the Applicant to substantiate the requirement of “no exports” by them in the original period of investigation
 - iii. The Applicant has made an incomplete relationship declaration and failed to establish / clarify the nature and extent of their relationship with M/s Qinhuangdao Yaohua Glass Machine Manufacture Company Ltd. (“QYGMMC”).
 - iv. No details have been provided whether it is a new plant or an old plant taken over by the producer,
- b. The Applicant has claimed excessive confidentiality and failed to provide reasons for claims of confidentiality on certain documents and no reasons have also been provided as why the same is not susceptible to summarization. Applicant has not provided non confidential version of some documents and contract with QYGMMC. Meaningful non-confidential submissions were not provided either.
- c. Under Rule 22, the Applicant was required to show that it is not related to *any* exporter or producer ‘for all the countries for which duty on the product was applicable’.
- d. The law on Rule 7 has been very well clarified by the Hon’ble Supreme Court in the case of Sterlite industries and thereafter by the Hon’ble Tribunal. It has also been clarified by the Hon’ble Tribunal that every information is not by itself required to be treated as confidential merely because a party in the course of investigation provides it to the Designated Authority on a confidential basis.
- e. The Applicant did not fulfill the pre-conditions of Rule 22 of the AD Rules. Appropriate and sufficient materials were not placed before the Designated Authority as a pre-condition for initiation under Rule 22 to initiate new shipper review. It is necessary under Rule 22 that the Applicant in the exporting country must not have exported the subject goods to India during the period of investigation and should not be related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. The “exporting country” is not limited to the country under investigation but includes all countries against whom duty has been imposed by the Authority with respect to the PUC.
- f. The Applicant made false declarations concerning its related Chinese entity, QYGMMC, to circumvent duties. QYGMMC has investments in several Float Glass lines in China, is a shareholder of the Applicant and is subject to anti-dumping duties as per Notification No. 47/2015-Customs (ADD) dated 08.09.2015. The Applicant did not bring this fact on record.
- g. It is certain that if the alleged disclosures which were subsequently made by the Applicant through letters, written submissions and rejoinder about the Chinese shareholding company had been made known to the Designated Authority prior to initiation, the case would not have been initiated. Such

suppression of material facts and conduct of the Applicant clearly show the malafide intent in securing an unwarranted initiation.

- h. The period of investigation, fixed as 9 months from 1st July 2015 to 31st March 2016, is arbitrary. Fixation of such shorter period of 9 months is contrary to Trade Notice of the Designated Authority specifying that the minimum period of investigation shall be 12 months. Further, the period of investigation selected is prospective. The Designated Authority, under Rule 22, is not empowered to determine such a prospective period of investigation. The law in this regard is clearly laid down in H&R Johnson where the Tribunal had held that selection of prospective period is unwarranted and would distort the entire scheme and purpose of imposition of anti-dumping duty to the grave disadvantage of the domestic industry that had earned the protection of anti-dumping duty.
- i. The exporter has not submitted proper non-confidential version of the response by claiming excessive confidentiality without any proper justification. Domestic industry claims that it has been done to ensure that they are not in a position to comment upon or to bring inadequacies in their submissions.
- j. It is submitted that the New Shipper has not clarified the discrepancy regarding allotment of shares in lieu of cash in the annual report and the response filed by them. Thus nondisclosure of complete information is a clear act of non-cooperation that too with the intent to mislead the authority and impede the investigations. The response of the new shipper should be rejected for non-compliance with the requirement of law and non-disclosure of information.
- k. In view of Rule 22 of AD Rules, the authority is obliged to analyse the relationship of Chinese company with Tariq Float Glass Limited (Pakistan). Since the new shipper from Pakistan is related to producer/exporter in China and the Chinese entity, NSR needs to be terminated.
- l. In the case of H&R Johnson India Ltd. v Designated Authority, 2005 and the findings of Designated Authority in the case of Compact Fluorescent Lamps(CFL), it has been stated that authority may collect information with regard to evidence pre-initiation and during the course of investigation. In view of this the domestic industry reiterates that authority should verify Yaohua Glass Group Corporation, China to ascertain the nature and structure of the relationship between Tariq and Yaohua Group.

F. Examination by the Authority

12. The Authority initiated the New Shipper Review keeping in view the provisions of Rule 22 of the AD Rules, which reads as follows:

“Rule 22

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee form the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review”.

13. Rule 22 specifies the circumstances under which a New Shipper Review investigation is to be carried out for the purpose of determining individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied:

- (a) that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
 - (b) that the exporter or producer shows that it is not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
14. It is evident from the above that the intention under Rule 22 is to determine individual dumping margin in respect of an exporter or producer who did not export the subject goods during the period of investigation of the original investigation. Since such producer/exporter did not export subject goods to India during the period of investigation of the original investigation, the Authority could not have determined individual dumping margin in respect of its exports at the time of original investigation. The purpose of new shipper review provision is, therefore, to provide an opportunity to such producer/exporter to claim individual dumping margin considering that these exporters have been granted residual dumping margin during the original investigation.
 15. In the instant case, M/s Tariq Glass Industries Ltd., Pakistan filed an application before the Authority seeking individual dumping margin and requested for initiating the new shipper review.
 16. The basic requirements for initiating the New Shipper Review under Rule 22 are that (a) anti-dumping duty is applicable on the subject goods and (b) the exporters or producers who are seeking determination of individual margin of dumping must not have exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation and they must show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the subject goods. The new shipper applicant who is seeking review, apart from making a declaration in the application that he fulfils the above conditions set out in Rule 22, cannot adduce any evidence at the time of making the application that he had not exported the goods during the period of investigation of the original investigation and that he is not related to the exporters/producers in the exporting country who are subject to anti-dumping duty on the subject goods. The Authority is not required to conduct a detailed enquiry prior to initiating new shipper review but is required to be *prima facie* satisfied that the conditions of Rule 22 are fulfilled. Unless there is material adverse evidence to contradict the statements made in the application, then the Authority may not refuse to initiate the new shipper review. In the present case, on the date of initiation of new shipper review, there was no material on record to show that the statements made by M/s Tariq Glass Industries Ltd, Pakistan (Producer and exporter) were not correct. Therefore, it cannot be said that there was no *prima facie* satisfaction on the part of Authority before initiating the new shipper review and accordingly, the initiation of the new shipper review is in order.
 17. The claims with regard to eligibility of the applicant as new shipper were examined to know whether the company had, directly or indirectly, exported the product to India during the period of investigation of the original investigation. The applicant was asked to establish its claim that the applicant or any of its related company had not exported the product concerned to India in the period of investigation of the original investigation. The Applicant provided certification stating that:
 - a. The Applicant did not export the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation;
 - b. The Applicant is not related to any exporters or producers in Pakistan who had exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation;
 - c. The Applicant is not related to any exporters or producers in Saudi Arabia, UAE, China, Indonesia and Iran who had exported the subject goods to India during the period of investigation in the investigations against these countries;
 - d. The related companies of the Applicant did not engage in the manufacture of the subject goods;
 - e. The related companies of the Applicant are not related to any exporter or producer in Pakistan who had exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation;
 - f. The related companies of the Applicant are not related to any exporters or producers in Saudi Arabia and UAE who are subject to anti-dumping duty;

The Authority considered the submissions of the Domestic Producers in this regard, but did not find any adverse material against the Applicant's claim of being a new shipper.

18. With respect to the issue regarding the relationship of the Applicant with a Chinese company, M/s.QinuangdaoYaohua Glass Machine Manufacture Company Ltd ("QYGMMC"), the Authority notes as under:

- a. Article 9.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement reads as follows:

9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. ...

- b. The authority notes that requirement under Article 9.5 is to show that the Applicant (who is a producer-exporter based in Pakistan) has not exported the product concerned to India during the period of investigation of the original investigation and is not related to any of the exporters or producers in Pakistan who have exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation and who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned. The Applicant has clearly satisfied this requirement that they are not related to any producer/ exporter in Pakistan who have exported the subject goods to India during the period of investigation of the original investigation or are subject to antidumping duties on the subject goods.
- c. The Authority notes the concerns of the Domestic Producers with respect to likelihood of circumvention and has, therefore, examined the relationship between the Applicant and QYGMMC. The Authority finds that the relationship between the Applicant and QYGMMC is purely contractual and the ownership of shares by QYGMMC is incidental to the contract entered into between the Applicant and QYGMMC for supply of plant and machinery. The relation between QYGMMC and the Applicant is one of service provider and service receiver.
- d. The Authority also notes that the Annual Reports of the Applicant list the related companies of the Applicant. It is further noted that the list of related companies does not mention QYGMMC.
- e. The Domestic Producers have not established any meaningful 'relationship' between the Applicant and QYGMMC, a Chinese entity. The Authority finds that a contractual relationship is insufficient to establish "relation" for the purpose of Rule 22.
- f. Further, the shareholding of QYGMMC is less than 5%, which is insufficient to show a controlling interest. No Directors are appointed on the Applicant's Board of Directors by QYGMMC by virtue of the shareholding. The Applicant and QYGMMC are not under any common management or control and the manufacturing process or business of the Applicant is in no way dependent on QYGMMC. No products of the Applicant are sold or transferred to QYGMMC.
- g. In light of the above, the Authority notes that QYGMMC is not related to the Applicant under Rule 22 of the AD Rules.
19. During the investigation the Authority neither found any evidence regarding relationship of the Applicant with any of the exporters or producers in Pakistan, who are subjected to anti-dumping duty nor any material evidence in this regard was brought before the Authority by any of the interested parties. The Authority, therefore, notes that the New Shipper Review investigation was initiated as per provisions laid down in Rule 22 of the AD rules which is in conformity with article 9.5 of the WTO AD Agreement. Further, the Authority also finds that the Applicant is not related to any exporter / producer based in any of the countries on which duty is applicable.
20. As regards the period of investigation, the Authority is well within its bounds to determine a period shorter than 12 months, but longer than 6 months. In the case of a New Shipper, it is not uncommon for a shorter period of time to be considered as the period of investigation. It is pertinent to mention here that the period selected is partially retrospective and partially prospective. The Authority notes the Domestic Producer's concerns regarding the risks of selecting a prospective period of investigation and indeed, the concerns are very valid. However, the factual situation of the present case is clearly distinguishable from the factual situation of the *H&R Johnson (2007)* case cited by the Domestic producers. In the *H&R Johnson (2007)* case, the CESTAT clearly noted the invalidity of the initiation of the new shipper review on the following grounds:

- i. The new shippers had not even begun production or exportation to India at the time of filing the new shipper review application.
 - ii. The new shippers were found to be ineligible for initiating a new shipper review under Rule 22.
 - iii. The entire period of review was prospective.
21. In the initiation of the subject review, the Authority was mindful of these requirements, as laid down by the CESTAT in *H&R Johnson (2007)* case and carefully considered these issues prior to initiation of the subject review. The Authority noted that the Applicants herein had begun production and exports to India in substantial quantity prior to the filing of the new shipper review application. The period selected is part retrospective and part prospective. Further, given the purport of Rule 22 of the AD Rules, it is noted that in a new shipper review, the entire period of investigation cannot always be retrospective. Thus, the selection of the period of investigation is justified.
22. The Authority notes that the Applicant began production of the subject goods subsequent to the period of investigation of the original investigation. The Authority notes that the primary business of the Applicant is the production and sales of all types and kinds of glass products, including the subject goods. The Applicant fired up their furnace and began commercial production of the subject goods in April 2013. The finished product is sold by the Applicant directly to unrelated companies in the domestic market as well as in the export market. There are only two principal shareholders / owners of the Applicant Company who are private individuals. The Authority also notes that the Applicant has three affiliate companies in Pakistan and all three of them have certified that they are not engaged in the manufacturing of the PUC and are not related to producers and exporters in Pakistan, Saudi Arabia or UAE who had exported the PUC to India during the period of investigation of the original investigation.
23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file.

G. Methodology for determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

NORMAL VALUE

25. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, normal value in relation to an article means:
 - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

General Methodology for working out Normal Value

26. It was first determined by the Authority whether the total domestic sales of the subject goods by the Applicant is representative when compared to the exports of the subject goods to India.
27. Thereafter, it was examined whether their sales are under ordinary course of trade in terms of Para 2 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. The producer and exporter has provided transaction wise details of sales made in home market and same have been accepted by the Authority, the said information has been relied upon to determine the normal value of the subject goods sold in the home market.
28. For conducting ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the information provided by the Applicant and compared with domestic selling price to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. The authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value where profit making transactions are more than 80% and in case where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.
29. While arriving at the net export price Authority relied on the DGCI&S transaction wise data in order to verify the correctness of data/information filed by the New Shipper applicant. It is further noted that comparison was made at the same level to arrive at the dumping margin.

NORMAL VALUE FOR APPLICANT

30. The Authority notes that the Applicant has submitted Exporter's Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of production of subject goods during the POI. All the sales in the domestic market were made directly to independent customers. Applicant has reported total domestic sales of *** of subject goods for the gross invoice value of ***. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. All domestic sales transactions have been considered for determination of the normal value. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods and determined whether profit making transactions are more than or equal to 80% or not. Since, the profit making transactions were less than 80%, authority has only considered profit making transactions for determination of normal value.
31. Applicant has claimed adjustment on account of rebates, commission, packing cost and credit cost. The Authority has allowed the adjustments as claimed and determined the normal value at ex-factory level in respect of the Applicant. The Normal Value so determined has been mentioned in the dumping margin table appended below.

EXPORT PRICE

32. As per the Exporter's Questionnaire, during the POI, the Applicant **exported *** MT** of subject goods to India for the gross invoice value of ***.directly to independent customers in India. The Applicant has claimed adjustments for inland freight, port handling expenses and bank charges. The Authority has allowed the adjustments as claimed and determined the export price at ex-factory level in respect of the Applicant. The net export price of the subject good was compared with the normal value arrived for the Clear Float Glass without packing based on the verified data/information and further corroborated with the DGCI&S transaction wise data. Details of the same are mentioned in the dumping margin table appended below.

DUMPING MARGIN

33. Comparing the aforesaid normal value and export price as determined, the individual dumping margin determined for the Applicant during the POI is as follows:

<u>Country</u>	<u>Exporter / Producer</u>	<u>Normal Value(US\$)</u>	<u>Net Export Price(US\$)</u>	<u>Dumping Margin(US\$)</u>	<u>Dumping Margin (%)</u>	<u>Dumping Margin Range</u>
<u>Pakistan</u>	M/s Tariq Glass Industries Ltd	***.	***.	***.	***.	<u>5 -15</u>

Comments on Disclosure**Post Disclosure Statement submissions by the Applicant**

34. Applicants adopt all the submissions made during the course of the investigation and submitted that if there is any change in the essential facts under consideration as presented in the disclosure statement, a personal hearing must be mandatorily granted by the Authority to the Applicant along with an opportunity to make comments.

Post Disclosure Statement submissions by the domestic industry

35. The following submissions were made by the domestic industry:
- Initiation of the investigation in this case itself is without jurisdiction inasmuch as the applicant industry has resorted to sheer manipulation to get the investigation initiated.
 - Domestic Industry has time and again requested the Authority to verify and check the genuineness of the export prices reported for the POI as 13mm products are exported at lower prices and kindly check the prices offered by Tariq Glass to other countries during the same period.
 - The Authority has no jurisdiction in the present matter due to lapse of time as maximum period available to the Authority to conclude the investigation is 18 months in terms of Rule 17 and the same has expired.

Examination by the Authority

36. The Authority notes that post-disclosure comments/submissions made by the interested parties are mostly reiterations of earlier submissions, which have already been examined suitably and properly addressed in the disclosure statement or in the relevant paragraphs of the present finding and therefore for the sake of brevity all of them are not repeated hereunder. The authority further considers appropriate to address some of the issues raised by the interested parties herein below:
- With regard to the submission of the Domestic Industry regarding the pricing of Clear Float Glass of 13 mm thickness, the authority notes that pricing of 13mm clear float glass has no relevance in the present investigation as the same is not part of the product under consideration. Further, prices of different thicknesses are determined based upon the market demand and supply and it is not correct to compare the price of one particular thickness with the price of other thicknesses. The claim of the domestic industry also

does not bear any merit because they have not been able to demonstrate that the price of 13mm thickness clear float glass supplied by Tariq Glass is lower as compared to the price of 13mm thickness clear float glass imported from other countries. Thus, there is no reasonable basis to correlate the prices of subject goods with the Clear Float Glass of 13mm thickness supplied by the Applicant.

- b) The Authority has examined the genuineness of the export prices reported by the Applicant from the DGCI&S data for exports to India and also compared the same with prices offered by Tariq Glass to other countries during the same period. The authority notes that there no significant variation between the export price to India and other countries for the product under consideration. Accordingly, there is no merit in the contention of the Domestic Industry.
- c) With regard to the submission of Domestic Industry on completion of New Shipper Review Investigation, the authority notes that the final findings of the New Shipper Review investigations have been completed as per provisions stipulated in Anti-Dumping Rules.

Final Findings and Recommendations of the Authority

37. After considering the foregoing the Authority concludes that

- i) Export price of Clear Float Glass exported to India produced by M/s Tariq Glass Industries Ltd, Pakistan is below its normal value during the period of investigation.
- ii) The Authority, therefore, recommends the anti-dumping duty of USD *** per MT be imposed on imports of “Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12 mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000” falling under Chapter 70 of the Custom Tariff Act, 1975 produced and exported by M/s Tariq Glass Industries Ltd, Pakistan

38. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority